

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली/निर्णय व डिक्री/47/2019

1. परबतसिंह पुत्र स्व. श्री बींजराजसिंह, उम्र 66 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी सरदार समंद फार्म पोस्ट दुदिया, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)
2. नरपतसिंह पुत्र स्व. श्री बींजराजसिंह, उम्र 61 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी सरदार समंद फार्म पोस्ट दुदिया, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)
3. श्रीमती कंचनकंवर पत्नी श्री चंद्रसिंह, पुत्री स्व. श्री बींजराजसिंह, उम्र 64 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी तिलोली, तहसील आसींद, जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... अपीलार्थीगण

ब नाम

1. हिज हाईनेस श्री महाराजा साहब श्री गजसिंहजी साहब, पता :- उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर (राज.)
2. राज. राज्य जरिए भूमिधारी तहसीलदार, पाली (राज.)

..... रेस्पोंडेण्ट्स

उपस्थिति :-

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थी ।
2. सरकारी पैरोकार ।
3. रेस्पोंडेण्ट संख्या एक बाद तामील अनुपस्थिति ।

निर्णय

दिनांक : 16/01/2020

gllh

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

1. उपरोक्त अपील धारा 223 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पाली बमुकदमा राजस्व वाद संख्या 37ए/16 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.5.19 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्ट्स को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलार्थी की ओर से लिखित बहस

पेश की गई, साथ ही मौखिक बहस भी की गई। अपीलार्थी व सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया था कि ग्राम भांबोलाई के खसरा नम्बर 23 में अपीलाण्ट के कब्जे-काश्त की 50 बीघा भूमि वाद-पत्र के पद संख्या एक में वर्णित अनुसार स्थित है, जिस पर अपीलाण्ट का 50-55 वर्षों से लगातार अपने पूर्वजों के समय से कब्जा-काश्त है। यह जमीन रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने दिनांक 24.12.69 को विधिवत् दस्तावेज के जरिए अपीलाण्ट के पूर्वज बींजराजसिंहजी को सुपुर्द की थी, उक्त दस्तावेज के द्वारा कब्जा सुपुर्द किया गया था। यह आदेश रेस्पोडेण्ट संख्या एक के कण्ट्रोलर ऑफ हाउस होल्ड, मारवाड़ जोधपुर दरबार की ओर से जारी किया गया था तब से कब्जा-काश्त लगातार अपीलार्थी का ही है। उक्त आदेश द्वारा दिनांक 5.4.91 को तहसीलदार के समक्ष म्यूटेशन खोलने के लिए आवेदन भी किया था, जिस पर पटवारी की रिपोर्ट मांगी गई। पटवारी द्वारा यह कहा गया कि लिखत अनरजिस्टर्ड है इसलिए म्यूटेशन स्वीकृत नहीं हो सकता है। सन् 1992 में समस्या समाधान शिविर में रेस्पोडेण्ट संख्या एक की ओर से श्री जिला कलेक्टर महोदय, पाली को इस संबंध में खातेदारी देने बाबत लिखा गया था कि जिन-जिन व्यक्तियों को भूमि का कब्जा दिया गया है, उनके नाम म्यूटेशन कर दिया जावें, फिर भी म्यूटेशन नहीं किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या एक के अधिकारी व कर्मचारी कब्जा हटाने आये थे। हर वर्ष अपीलाण्ट ही काश्त करता है एवं फसल लेता है। रेस्पोडेण्ट संख्या एक का कभी भी कब्जा-काश्त नहीं रहा है। खसरा नम्बर 23 बड़ा रकबा है, जिसमें अपीलाण्ट के अलावा कई व्यक्तियों का अलग-अलग रकबे पर कब्जा है। इसका लगान भी सभी काबिज व्यक्ति काबिज रकबे अनुसार राज्य सरकार को शुरू से ही अदा करते आ रहे हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने लिखित में पत्र जिला कलेक्टर व तहसीलदार को दिया था कि लगान सभी काबिज व्यक्तियों से वसूल



9/11/21
राजस्थान का जिला प्राधिकारी
पाली

किया जावें। अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार देने एवं कब्जा अपीलान्ट का होने बाबत भी रेस्पोजेण्ट संख्या एक ने पूर्व में राज्य सरकार व जिला कलेक्टर को लिखा था। अपीलान्ट का कब्जा वाद के साथ संलग्न नक्शे में दर्शित भूमि पर लगातार चला आ रहा है इसलिए विधिनुसार अपीलान्ट उपरोक्त भूमि की खातेदारी पाने का अधिकारी है, साथ ही अपीलान्ट के कब्जे-काश्त, उपयोग-उपभोग में रेस्पोजेण्ट संख्या एक दखल नहीं करें, इस बाबत स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी की ओर से साक्ष्य के रूप में शपथ-पत्र पेश किया गया था। रेस्पोजेण्ट्स की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।



3. रेस्पोजेण्ट की ओर से एक आवेदन आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का इस आशय का पेश किया गया कि उपरोक्त भूमि वर्तमान में रेस्पोजेण्ट संख्या एक के खातेदारी की राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं रेस्पोजेण्ट संख्या एक के विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी, सोजत के न्यायालय में पुराने एवं नए सीलिंग कानून के तहत प्रकरण संख्या 35/71 व 227/73 लंबित है इसलिए सीलिंग अधिनियम 1973 की धारा 36 अनुसार वाद सुनवाई की अधिकारिता नहीं है इसलिए वाद खारिज किया जावें।

4. अधीनस्थ न्यायालय में उपरोक्त आवेदन का अपीलान्ट की ओर से विधिवत् जवाब पेश किया गया था तथा दौराने बहस इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 1991 आर.आर.डी. पेज 397 एवं 1985 आर.आर.डी. पेज 96 पेश किए थे, जिसमें माननीय राज. उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 36 सीलिंग अधिनियम केवल उसी मामले में लागू होते हैं, जब प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सीलिंग मुकदमे में दिए गए निर्णय को सिविल अथवा राजस्व न्यायालय में कोई व्यक्ति चुनौती देता है अन्य किसी प्रकरण में सिविल अथवा राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित नहीं है, साथ ही खातेदारी अधिकार एवं घोषणा

9/11/11
राजस्व न्यायालय प्राधिकारी
पाली

हेतु राजस्व न्यायालय में वाद पेश करने पर किसी प्रकार का वर्जन नहीं होने बाबत भी फाईन्डिंग दी गई थी।

5. वकील अपीलान्ट ने धारा 36 के बाबत निवेदन किया कि, "धारा 36 सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन - (1) किसी भी सिविल अथवा राजस्व न्यायालय को किसी ऐसे प्रश्न अथवा मामले को विनिश्चित करने या उसमें कार्यवाही करने की कोई अधिकारिता नहीं होगी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्राधिकृत अधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय अथवा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (2) किसी भी सिविल अथवा राजस्व न्यायालय को भूमि अंतरण के किसी संविदा के यथावत् पालन के निमित्त किसी ऐसे वाद को ग्रहण करने अथवा उसमें कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं होगी, जो इस अधिनियम के अधीन अधिशेष भूमि पर राज्य सरकार के अधिकार को प्रभावित करता है।"

6. उपरोक्त धारा 36(1) में दिए गए प्रावधान अनुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए जाने वाले विनिश्चय अथवा कार्यवाही के प्रश्न एवं मामले को विनिश्चित करने की अधिकारिता सिविल व राजस्व न्यायालय को नहीं होने बाबत प्रावधान है। इसी तरह धारा 36(2) में किसी अंतरण की संविदा के पालन का वाद सिविल व राजस्व न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा। उपरोक्त धारा 36 के दोनों उपधारा में इस बाबत कहीं भी रोक अथवा वर्जन नहीं है कि किसी तीसरे व्यक्ति के खातेदारी अधिकार विधिनुसार उत्पन्न हो गए हो, तो वह उसकी घोषणा का वाद पेश नहीं कर सकता हो।

7. अपीलान्ट ने न्यायिक दृष्टांत 1991 आर.आर.डी. पेज 397, 1985 आर.आर.डी. पेज 96, 1980 आर.आर.डी. पेज 93 एवं धारा 19(1ए) के प्रावधान पेश किए और यह बताया कि दिनांक 29.12.79 को टिनेन्सी एक्ट में उक्त धारा जोड़ी गई है, जिस अनुसार जो व्यक्ति दिनांक 31.12.69 को वार्षिक रजिस्टर में खुद काश्त का टिनेन्ट या



1/11/11
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सब टिनेन्ट दर्ज है या कोई व्यक्ति वार्षिक रजिस्टर में दर्ज नहीं है, लेकिन खुद काशत का टिनेन्ट अथवा सब टिनेन्ट है, तो उसे खातेदारी अधिकार दे दिए जाएंगे। इसके अलावा वकील अपीलाण्ट ने धारा 19(2ए) व 19(3) राज. टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों एवं 1987 आर.आर.डी. पेज 304, 1988 आर.आर.डी पेज 585 के न्यायिक दृष्टांत पेश करते हुए निवेदन किया कि इस संबंध में खातेदारी उद्घोषणा का वाद लाने हेतु किसी प्रकार की कोई मयाद नहीं है और धारा 19 के तहत कोई व्यक्ति अंदर मयाद आवेदन नहीं करता है, तो भी वह खातेदारी का ही दावा कर सकता है।

8. वकील अपीलाण्ट ने यह भी निवेदन किया कि रेस्पोंडेण्ट संख्या एक व दो द्वारा अनेकानेकबार वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् अनुसार अपीलाण्ट का कब्जा व काशत होना स्वीकार करते हुए खातेदारी अधिकार दिए जाने की अनुशंषा की है एवं लगान भी अपीलाण्ट से काबिज भूमि का सन् 1963 से आज दिनांक तक वसूल करते आ रहे हैं। उपखण्ड अधिकारी द्वारा भूमिधारी को काबिज व्यक्तियों की सूची, जो रेस्पोंडेण्ट संख्या एक द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी, उसमें वर्णित व्यक्तियों से लगान वसूल किए जाने बाबत आदेश पारित किया गया था, जिसकी अनुपालना में भूमिधारी द्वारा काबिज व्यक्ति अपीलाण्ट वगैरह से लगान अब तक वसूला गया है। लगान केवल खातेदार से ही वसूल कर सकते हैं इस कारण से भी अपीलाण्ट खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

9. इसके अलावा अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह भी निवेदन किया कि उपरोक्त समान मामले अर्थात् इसी अपील में वर्णित खसरे की भूमि के संबंध में अन्य व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग 8 वाद-पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किए थे, जहां से खारिज होने पर 8 अलग-अलग अपीलें श्रीमान् के न्यायालय में अपील संख्या 35/14 से 42/14 पेश हुई थी, जो श्रीमान् के न्यायालय द्वारा दिनांक 4.7.14 को निर्णित होकर स्वीकार करते हुए उपरोक्त प्रकरणों में वर्णित व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार दिए जाने बाबत निर्णय व डिक्री पारित किए



guler
राज्य अपील प्राधिकारी
पटना

गए थे, जिसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अपील नहीं हुई एवं वे निर्णय व डिक्री अंतिम रहे। उपरोक्त अपीलें भी समान तथ्यों पर, समान भूमि के संबंध में, समान पक्षकारों के बीच है इस कारण से भी अपील स्वीकार योग्य है।

10. समान मामलों में ही अन्य व्यक्तियों द्वारा रेस्पोजेण्ट संख्या एक की भूमि के संबंध में सहायक कलेक्टर, पाली के न्यायालय में वाद संख्या 22/95 बनेकंवर बनाम महाराजा गजसिंह और वाद संख्या 23/95 भरतसिंह बनाम महाराजा गजसिंह दिनांक 12.3.99 को डिक्री किए गए और इसी आधारों पर खातेदारी अधिकार दिए गए, जिसका राजस्व रेकॉर्ड में अंकन हो चुका है और निर्णय व डिक्री को आज दिनांक तक कभी भी चुनौती नहीं दी गई है इस कारण भी अपील स्वीकार योग्य है।

11. सरकारी पैरोकार की ओर से निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिवत् पारित किए गए हैं। जब तक सीलिंग का मामला लंबित है, तब तक खातेदारी घोषणा का वाद पोषणीय नहीं है इस कारण से अपील मय खर्चा खारिज की जावें।

12. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम धारा 19(1ए), 19(2ए), 19(3) राज. टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों का अवलोकन किया गया। धारा 19(1ए) को दिनांक 29.12.79 को संशोधन के जरिए जोड़ी गई है, जिस अनुसार जो व्यक्ति दिनांक 31.12.69 को वार्षिक रजिस्टर में खुद काशत का टिनेन्ट या सब टिनेन्ट दर्ज है अथवा कोई व्यक्ति जो वार्षिक रजिस्टर में दर्ज तो नहीं है, लेकिन खुद काशत का टिनेन्ट अथवा सब टिनेन्ट है तो उसे खातेदारी अधिकार दे दिए जाएंगे इस संबंध में दो वर्ष में आवेदन प्रस्तुत किए जाने के प्रावधान है। इसी तरह धारा 19(2ए) और धारा 19(3) को भी दिनांक 29.12.79 को संशोधित किया गया है। इस संबंध में अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक



11/11
राजस्थान अपील प्राधिकारी
पाली

दृष्टांत 1987 आर.आर.डी. पेज 304, 1988 आर.आर.डी. पेज 585 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के दौरान धारा 19 के तहत आवेदन पेश नहीं करता है, तो वह व्यक्ति धारा 88 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत कभी भी वाद प्रस्तुत कर सकता है और अपना अनुतोष अर्थात् खातेदारी प्राप्त कर सकता है।

13. जहां तक आवेदन आदेश 7 नियम 11 में वर्णित धारा 36 सीलिंग अधिनियम का प्रश्न है, धारा 36 इस प्रकार है, "धारा 36 सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन - (1) किसी भी सिविल अथवा राजस्व न्यायालय को किसी ऐसे प्रश्न अथवा मामले को विनिश्चित करने या उसमें कार्यवाही करने की कोई अधिकारिता नहीं होगी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्राधिकृत अधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय अथवा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (2) किसी भी सिविल अथवा राजस्व न्यायालय को भूमि अंतरण के किसी संविदा के यथावत् पालन के निमित्त किसी ऐसे वाद को ग्रहण करने अथवा उसमें कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं होगी, जो इस अधिनियम के अधीन अधिशेष भूमि पर राज्य सरकार के अधिकार को प्रभावित करता है।" धारा 36(1) में दिए गए प्रावधान अनुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए जाने वाले विनिश्चय अथवा कार्यवाही के प्रश्न एवं मामले को विनिश्चित करने की अधिकारिता सिविल व राजस्व न्यायालय को नहीं होने बाबत प्रावधान है। इसी तरह धारा 36(2) में किसी अंतरण की संविदा के पालन का वाद सिविल व राजस्व न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा। उपरोक्त धारा 36 के दोनों उपधारा में इस बाबत कहीं भी रोक अथवा वर्जन नहीं है कि किसी तीसरे व्यक्ति के खातेदारी अधिकार विधिनुसार उत्पन्न हो गए हो, तो वह उसकी घोषणा का वाद पेश नहीं कर सकता हो।

14. इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पेश किया, में 1991 आर.आर.डी. पेज 397 में माननीय राजस्व मण्डल ने स्पष्ट रूप



9/11/11
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

से धारा 36 की व्याख्या करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि "(b) Raj. Imposition of Ceiling on Afrl. Holding Act, 1973 (New Ceiling Law), Section 36 - The Section bars the jurisdiction of civil or revenue courts only in respect of matters required to be decided or dealt with by the Authorised Officer - Declatarion of Khatedari or issue of injunction is not to be decided by ceiling authorities and, therefore, the jurisdiction of the civil or revenue courts in such matters is not barred"

इस तरह से उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में पैरा संख्या 10 में भी यही अभिनिर्धारित किया गया है कि खातेदारी घोषणा एवं निषेधाज्ञा का दावा राजस्व न्यायालय द्वारा ही सुना जाएगा। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के पैरा संख्या 12 में भी यही व्यवस्था तय की हुई है।



15. दूसरा न्यायिक दृष्टांत 1985 आर.आर.डी. पेज 96 में माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा पैरा संख्या 4 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "thus, first of all respondent number 6 & 7 can be asked to surrender the excess land out of land which is in there possession. If the obligation of res. no. 6 & 7 for any reason can not be enforced against in respect of the land in there possession then it would be open to the petitioners to enforced there right by resorting to the remedy of a suit for decleration and injunction not only against res. no. 6 & 7 but also against State of Rajasthan."

9/11/11
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

16. इसके अलावा 1980 आर.आर.डी. पेज 93 के न्यायिक दृष्टांत में माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अगर सीलिंग कानून के तहत निर्णय होकर भूमि अधिग्रहण के आदेश दे दिए गए हो और अंतरणों को मान्यता नहीं दी गई हो, तो वे क्रेतागण भी राज. टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत वाद पेश

करने हेतु स्वतंत्र है और वाद पेश कर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों अनुसार एवं धारा 36 अनुसार किसी भी दस्तावेज के आधार पर कोई भी व्यक्ति खातेदारी घोषणा का वाद राजस्व न्यायालय में वाद पेश करने हेतु किसी प्रकार का कोई वर्जन नहीं है, भले ही सीलिंग का मुकदमा लंबित हो, केवल उक्त प्रावधान के तहत व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी के विनिश्चय को चुनौती नहीं दे सकता है। वकील अपीलान्ट के उक्त कथन कि हस्तगत प्रकरण में तो जिस सीलिंग मुकदमे का वर्णन रेस्पोजेण्ट संख्या दो ने आदेश 7 नियम 11 के आवेदन में दिया गया है, उसमें केवल उपखण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा नोटिस जारी किए गए, जिसके विरुद्ध रेस्पोजेण्ट संख्या एक द्वारा माननीय राज. उच्च न्यायालय में रिट याचिका तत्समय से ही पेश है और उसमें अर्थात् सीलिंग कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही नहीं किए जाने बाबत स्थगन आदेश है ऐसी स्थिति में न तो कोई सीलिंग कानून के तहत निर्णय हुआ है, न ही भूमि अधिग्रहण की गई है। भूमि आज भी रेस्पोजेण्ट संख्या एक के खातेदारी में ही है। उपरोक्त तथ्यों का रेस्पोजेण्ट की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है।

17. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस अनुसार पूर्व में उपरोक्त भूमि रेस्पोजेण्ट संख्या एक के मालिकाना हक-हकूक, अधिकार की थी, लेकिन लैण्ड ऑनर एस्टेट एक्ट 1963 प्रभाव में आने के बाद भूमि के मालिकाना अधिकार खत्म करते हुए खातेदारी अधिकार दिए गए हैं। उपरोक्त भूमि रेस्पोजेण्ट महाराजा की मालिकाना थी, जिस पर अपीलान्ट का कब्जा व काश्त था। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के पद संख्या 17 से 19 में वर्णित तथ्यों का भी रेस्पोजेण्ट्स की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है। लगान लैण्ड ऑनर्स एस्टेट एक्ट 1963 प्रभाव में आने के समय से एवं उक्त अधिनियम को वर्ष 1975 में संशोधित किए जाने के समय से रेस्पोजेण्ट संख्या दो भूमिधारी द्वारा अपीलान्ट से ही वसूल किया जा रहा है इस बाबत उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश भी पारित किया गया है, साथ ही वर्ष 1974-75 में काश्त करने वाले व्यक्तियों के नाम राज्य

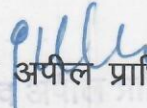


9/11/75
राजस्व अपील प्राधिकारी
मालवी

शुल्क वसूल कर अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड, जमाबंदी में बतौर खातेदार दर्ज करें, साथ ही रेस्पोंडेंट के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अपीलार्थी के कब्जे-काश्त, उपयोग-उपभोग में दखलंदाजी न तो स्वयं करें, न ही अन्य से करावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/01/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली (राज.)

डिकरी ब सीगे अपील

(ऑर्डर 41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "4" 9)

पीठासीन अधिकारी :- श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली / निर्णय व डिक्री / 47 / 2019

1. परबतसिंह पुत्र स्व. श्री बींजराजसिंह, उम्र 66 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी सरदार समंद फार्म पोस्ट दुदिया, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)
2. नरपतसिंह पुत्र स्व. श्री बींजराजसिंह, उम्र 61 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी सरदार समंद फार्म पोस्ट दुदिया, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)
3. श्रीमती कंचनकंवर पत्नी श्री चंद्रसिंह, पुत्री स्व. श्री बींजराजसिंह, उम्र 64 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी तिलोली, तहसील आसींद, जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... अपीलार्थीगण

ब ना म

1. हिज हाईनेस श्री महाराजा साहब श्री गजसिंहजी साहब, पता :- उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर (राज.)
2. राज. राज्य जरिए भूमिधारी तहसीलदार, पाली (राज.)

..... रेस्पोंडेण्ट्स

अपील संख्या 47 / 2019 बनाराजगी निर्णय व डिक्री अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पाली दिनांक 20.5.19 बमुकदमा

राजस्व वाद संख्या 37ए / 16

दावा बाबत 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह अपील बतारीख 16/01/2020 को रूबरू हमारे व बहाजिर श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थी, रेस्पोंडेण्ट संख्या एक अनुपस्थित एवं रेस्पोंडेण्ट संख्या दो सरकारी पैरोकार समायत होकर हुक्म हुआ कि लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किए जाते हैं तथा अपीलार्थी को ग्राम भाम्बोलाई के खसरा नंबर 23 रकबा 50 बीघा का खातेदार-काश्तकार घोषित किया जाता है और अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकॉर्ड, जमाबंदी में अमल-दरामद किए जाने और वाद में वर्णित अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करने का आदेश पारित किया जाता है। भूमिधारी तहसीलदार, पाली उपरोक्त निर्णय व डिक्री की पालना में अपीलार्थी से आज दिनांक की डी.एल.सी. दर से स्टाम्प ड्युटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूल कर अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकॉर्ड, जमाबंदी में बतौर खातेदार दर्ज करें, साथ ही रेस्पोंडेण्ट के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अपीलार्थी के कब्जे-काश्त, उपयोग-उपभोग में दखलंदाजी न तो स्वयं करें, न ही अन्य से करावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर मुहर अदालत आज तारीख 16/01/2020 को जारी किया गया।

मुहर अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली (राज.)
पाली